COUNCIL on FOREIGN RELATIONS

काउन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के कार्यकारी दल का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव को मजबूत बनाने के 'साझा अभियान' को सर्वोच्च प्राथमिकता दे.

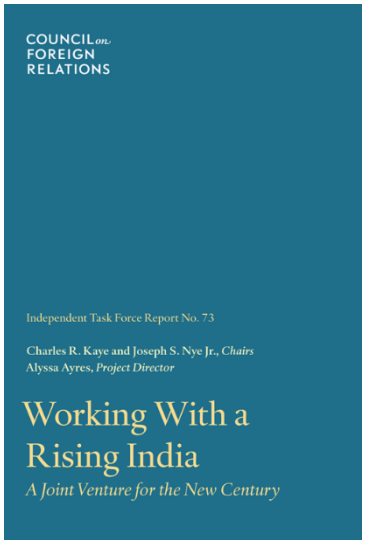

काउन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशंस द्वारा गठित एक स्वायत्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट, *उदय होते भारत के साथ उद्यम : नई सदी के लिए एक साझा अभियान* शीर्षक के प्रकाशित हुई है. यह रिपोर्ट कहती है, " उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ते भारत के पास अमरीका के हित में देने को बहुत से सकारात्मक अवसर हैं और यह विस्तार आगे आने वाले दो दशकों से अधिक समय तक चलने वाला है."

दुनिया के सबसे बड़े गणराज्य भारत ने पिछले दस वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों को निर्धनता की स्थिति से छुटकारा दिलाया है. यह देश हाल की मंदी के दौर से उबर कर फिर उठ खड़ा हुआ है, और चीन को पीछे छोड़ते हुए वह दुनिया का सबसे अधिक तेजी से आर्थिक विकास जुटा लेने वाला देश बन गया है. इस कार्यकारी दल का मानना है " यदि भारत अपने विकास की यह मौजूदा गति बनाए रखे और अकेले ही विकास की दर को दस से ऊपर ही संजोए रहे, तो निश्चित रूप से उसमें यह क्षमता है कि अगले दो या तीन दशकों में वह चीन की तरह दस लाख करोड़ अमरीकी डॉलर वित्तीय हैसियत वाला देश हो जाएगा."

भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक विकास की वरीयताएँ तथा विदेश नीतियों का पुनर्संगठन देश के आगे यह स्थिति रखता है कि देश या तो अपने सामने दिखने वाले उपलब्धिपूर्ण अवसरों का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करे या मौका चूक कर पिछड़ जाने का जोखिम उठाए. नरेन्द्र मोदी का कहना है " भारत को यह तय करना होगा कि वह वैश्विक व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन कर उसके साथ एक हो जाय. ऐसा करने से भारत की उत्पादन के क्षेत्र में अपनी मजबूत जगह बनेगी और उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी. अगर भारत यह विकल्प नहीं अपनाता है तो उसके लिए अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना बहुत कठिन हो जाएगा."

चूंकि भारत अपनी नीतिगत स्वायत्तता बनाए रखते हुए संयुक्त राज्य से अपना गठबंधन नहीं बनता है, ऐसी दशा में संयुक्त राज्य और भारत के संबंध का प्रारूप पारंपरिक ढाँचे से मेल नहीं खाएगा. इसी कारण से कार्यकारी दल यह अनुशंसा करता है " संयुक्त राज्य साझा अभियान के प्रारूप को अपनाते हुए भारत से संबंध बनाए. इस

प्रारूप में सहमतियों और असहमतियों के संयोजन और प्रबंधन की स्पष्ट व्यवस्था है इस प्रकार इसके माध्यम से दोनों देशों के पारस्परिक हितों की रक्षा की जा सकती है."

इस द्विपक्षीय कार्यकारी दल के अध्यक्ष चार्ल्स आर काय हैं. एक निजी इक्विटी फर्म के प्रमुख अधिकारी वारबर्ग पिंकस,संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के व्यापार संघ के निवर्तमान अध्यक्ष तथा हॉवर्ड केनेडी स्कूल के डीन तथा प्रोफ़ेसर रह चुके जोसेफ एस न्ये जूनियर इस कार्यकारी दल से संबद्ध हैं. काउन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशंस अलीस्सा अय्रेस के निर्देशन में काम करती है, जो कि भारत, पाकिस्तान तथा दक्षिण एशिया के वरिष्ठ कार्य सहयोगी है. इस कार्यकारी दल में सोलह महत्वपूर्ण विशेषज्ञ भागीदार हैं और यह सभी राजकीय, शैक्षिक तथा विविध गैर लाभ लक्षित संस्थानों से आये हैं.

यह कार्यकारी दल यह भी अनुशंसा करता है कि भारत के नीति निर्माता निम्नलिखित सन्दर्भों पर भी विचार करें:

- "ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के निराकरण के लिए, जो भारत के वैश्विक विकास के क्रम में बाधक हों, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में भारत की सहायता करे. भारत इस कदम को अपने ही हित का विषय मानते हुए स्वीकार करे, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच कम से कम विस्तृत व्यवसायिक लेन-देन ही शुरू हो."

- " अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य तथा अन्य बाहरी सैन्य तैनाती में कटौती, भारत की क्षेत्रीय असुरक्षा को लेकर चिंता का विषय है." यह कार्यकारी दल इस बात की पैरवी करता है कि संयुक्त राज्य अफगानिस्तान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करे. राष्ट्राध्यक्ष ओबामा ने अपना निर्णय यह लिया है कि अफगानिस्तान से फौजों की तैनाती को हटाने का काम धीरे धीरे ही किया जाय. यह दल यह सलाह देता है कि संयुक्त राज्य अफगानिस्तान में अपनी कम से कम 5000 टुकड़ियाँ 2017 तक बनी रहने दे.

- "कार्यकारी दल का मानना है कि भारत को अपनी सामाजिक और वित्तीय महत्वाकांक्षाओं को सफल बनाने के लिए स्त्रियों और बालिकाओं की राह में आये व्यवधानों को दूर करने का प्रयत्न करना होगा. हाल में वैश्विक संस्थान मेकेंजी द्वारा किया गया एक अध्ययन बताता है कि स्त्रियों के पक्ष को ध्यान में रख कर किया गया आर्थिक अभियोजन सत्तर हज़ार करोड़ से करीब तीन लाख करोड़ अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त लाभ हासिल कर सकता है.

इस कार्यकारी दल की अनुशंसा है कि संयुक्त राज्य तथा भारत के गठबंधन को द्विपक्षीय कार्यक्रम में सर्वोपरि रखने से भारत के आर्थिक विकास में अमेरिका का बेहतर सहयोग प्राप्त होगा. इस संविद गतिविधि के माध्यम से भारत तथा अमेरिका अपने अनेक आर्थिक विकास के लक्ष्य देख पाएंगे और नई दिल्ली तथा वाशिंगटन मिल कर उन्हें हासिल करने का रास्ता खोज पाएंगे. इसके लिए यह ज़रूरी है कि जिस तरह पिछले दशकों में भारत और संयुक्त राज्य ने रक्षा तथा अन्य नीतिगत मामलों में आपसी तालमेल बनाया वैसा ही आर्थिक सुधार की दिशा में भी बनाया जाय.

भारत और संयुक्त राज्य के बीच साझा हित और वैश्विक मामलों के कई मुद्दे हैं. इसी क्रम में इस कार्यकारी दल ने साझा अभियान के लिए चार प्रमुख क्षेत्र सुझाए हैं: कंप्यूटर/इंटरनेट का क्षेत्र, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य, मौसम में बदलाव की चुनौती, स्वच्छ ऊर्जा तथा लोकतंत्र का संरक्षण. कंप्यूटर/इन्टरनेट तथा वैश्विक स्वास्थ्य स्तर की दिशा में भारत ने प्रचुर तकनीकी दक्षता हासिल कर ली है. अमरीकी सहयोगियों के साथ भारत के विशेषज्ञ बराबरी से काम करते हुए निजी क्षेत्र के संचार तंत्रों और आयुर्विज्ञान संस्थानों में अपना कौशल प्रदर्शित कर रहे हैं.

इसके साथ साथ कार्यकारी दल ने इस बात पर भी बल दिया है कि संयुक्त राज्य भारत के साथ पूरे परिदृश्य को ध्यान में रख कर, सुरक्षा संबंधी मामलों में भी पारस्परिक विमर्श बढाए. इस सन्दर्भ में देश की आतंरिक सुरक्षा के साथ आतंकवादी घटनाओं से निपटने की कार्यवाही पर भी अतिरिक्त ध्यान दिया जाय.

कार्यकारी दल की पूरी पड़ताल तथा अनुशंसा के लिए "*उदय होते भारत के साथ उद्यम : नई सदी के लिए एक साझा अभियान*" की विस्तृत रिपोर्ट पढ़ें.

***

Task Force Members: कार्यकारी दल के सदस्य

अलीस्सा एर्ज़ (प्रोजेक्ट निदेशक), काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस
अजय बंगा, मास्टर कॉर्ड
सी फ्रेड बर्गस्टन, पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेश्नल इकोनोमिक्स
रॉबर्ट डी ब्लैकविल (सदस्य अनियुक्त), काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस
मार्शल एम बुटॉन, शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स
निकोलस बर्न्स, हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी
स्टीफेन पी कोहेन, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन
रिचर्ड फ़ॉन्टेन, सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सेक्योरिटी
सुमित गांगोली, इन्डियैना यूनिवर्सिटी,ब्लोमिंगटन
हेलेन डी गेल, मेकेंजी सोशल इनिशिएटिव
चार्ल्स आर केय (सह अध्यक्ष), वारबर्ग पिंकस एल एल सी
मैरी किसेल, वॉल स्ट्रीट जर्नल
जोसेफ एस नाय (सह अध्यक्ष), हॉवर्ड यूनिवर्सिटी
गैरी रफ़हैड, होवर इंस्टीट्यूशन
मैरिको सिल्वर,बेनिंगटन कॉलेज
एश्ली जे टेलिस, कार्नेगी एनडाऊमेंट फॉर इंटरनेश्नल पीस

***

काउन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशंस द्वारा प्रायोजित स्वायत्त कार्यकारी दल की रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुडी नीतियों और मामलों का विश्लेषण करती है और अनेक समाधान और सुझाव सामने रखती है. इस दल में विभिन्न क्षेत्रों और विषयों के विशेषज्ञों ने अपना योगदान दिया है.